

प्रेषक,

आर०के० सुधांशु,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून:

दिनांक: 07 फरवरी, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत मद प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सैनिक विश्राम गृह, खटीमा के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4003/सै.क./सै.वि.ग./खटीमा, दिनांक 12.12.2014 एवं शासनादेश संख्या-318/XXVII (1) /2014, दिनांक 18.03.2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैनिक विश्राम गृह, खटीमा के निर्माण हेतु गठित आगणन की औचित्यपूर्ण लागत रु० 59.47 लाख (सिविल कार्यों हेतु रु० 58.78 लाख + उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार किये जाने वाले कार्यों हेतु रु० 0.69 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में सैनिक विश्राम गृहों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-15, लेखाशीर्षक-4235 (आयोजनागत) में प्राविधानित धनराशि रु० 70.00 लाख (रु० सत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष रु० 20.00 लाख (रु० बीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वहन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
- 2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
- 3- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जायेगी।
- 4- विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 5- स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।
- 6- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- 7- आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 8- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- 9- व्यय की भौतिक/वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रत्येक माह की 07 तारीख तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 10- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-15 (आयोजनागत) के लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-0301-सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 11- उक्त स्वीकृत रू० 20.00 लाख (रू० बीस लाख मात्र) की धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार एलोटमेंट आई०डी०सं०-S1502150014, दिनांक 02 फरवरी, 2015 द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4732 में कर दिया गया है।
- 12- यह आदेश वित्त अनुभाग-1 के अशा० संख्या-108/XXVII(1)/2015, दिनांक 28 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर० के० सुधांशु)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या:-1221 (1) /XVII-3/14-09(65)/2005, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंहनगर।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
5. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रुद्रपुर, उधमसिंहनगर।
6. ✓ राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह राणा)
उप सचिव।